मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित खेल परिसर

3410. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों में खेल प्रतिभा के विकास के लिए मध्य प्रदेश में 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार कितने खेल परिसरों की स्थापना की गई है तथा वे खेल परिसर किन-किन स्थानों पर कब-कब स्थापित किए गए;

(ख) इनमें से प्रत्येक खेल परिसर में किन-किन खेलों का कब से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और कौन-कौन से खेलों के लिए विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षकों की कब से नियुक्ति की गई है;

(ग) इन खेल परिसरों के विकास के लिए खेल के मैदानों, प्रशिक्षण और खेल सामग्रियों के संबंध में क्या-क्या मानदण्ड और न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए हैं और किन-किन खेल परिसरों में इन मानदण्डों का पालन किया गया है;

(घ) इन खेल परिसरों के खिलाड़ी छात्रों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की किन-किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इनमें से कौन-कौन से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय प्रतिभा के रूप में मान्यता प्रदान की गई; और

(ङ) इन खेल परिसरों के कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन और इन्हें प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता-लक्ष्य प्राप्त करने की योजना

3411. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में 85 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई विशेष योजनायें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य में प्राथमिक , उच्च प्राथमिक और आरम्भिक कक्षाओं के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

सरकार उत्तर प्रदेश में निरक्षरता समाप्त करने के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर वर्ष 1993–94 के लिये अतिरिक्त नामांकन के लिये निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है :–

कक्षा 1 से 5	6.56 लाख
कक्षा 6 से 8	3.70 लाख

(घ) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण , पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों

के लिये अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का उद्देश्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आदि, देश में निरक्षरता उन्मूलन के व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बुनियादी शिक्षा परियोजना राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, इसका उद्देश्य सर्वव्यापी नामांकन तथा प्राथमिक शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करना है।

Differential Tariff for Visitors to Taj Mahal

@3412. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to levy differential tariff for visitors to Taj Mahal; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE

(a) Yes, Sir.

(b) Details are yet to be finalised.

Previously Unstarred Question 2112 transferred from 12th August, 1993.

राजभाषा के रूप में अंग्रेजी

3413. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषा अंग्रेजी है, यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इन राज्यों में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) इस संबंध में अल्पसंख्यक आयुक्त के बीसवें प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषा का ज्ञान रखने वाले और हिन्दी में निपुणता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अलग-अलग राज्यों में राजभाषा के निर्धारण के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी। अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग राज्यों में मुख्य तथा अल्पसंख्यक देशी भाषाओं को बोलने वालों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये हैं। तथापि, 1981 की